ग्रामोद्योग अयोग, खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, संस्थान तथा संस्थानों के संघ के साथ संयुक्त रूप से कच्चे माल की आपूर्ति, विपणन सहायता, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी सुधार, औद्योगिक संपदा की स्थापना इत्यादि के रूप में सहायता सेवाओं का जाल फैला रही है। अपने सामान्य कार्यक्रम के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 125 ब्लॉक विकास कार्यक्रम, जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम में मधुमक्खी पालन, हस्तनिर्मित कागज तथा चमड़ा जैसे विशेष कार्यक्रम भी चलाये हैं। बिहार में के वी आई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 125 ब्लॉक कार्यक्रम के अधीन 11 ब्लॉकों को चुना गया है तथा जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम के अधीन 4 जिलों को चुना गया है।

Annual growth in the industrial sector

3841. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are committed to maintain a 12% annual growth in the industrial sector;

(b) the growth rate of industrial production during the Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan;

(c) in what manner Government propose to achieve the 12% growth rate; and

(d) the details of measures taken in this regard so far?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The Common Minimum Programme of the Government has envisaged maintaining industrial growth at 12%. The growth rate of industrial production during Sixth, Seventh and Eighth Five Year Plan stood at 5.9%, 8.5% and 7.3% (expected).

(c) and (d) Sector specific strategies have already been initiated to remove constraints in under performing sectors. The credit policy announced recently by Reserve Bank of India is also expected to provide further impetus to industrial growth. Government has also proposed initiatives in the Union Budget 1997-98 for accelerated industrial growth. Domestic and foreign investment is encouraged in industry and infrastructure sectors.

Privatisation of BHEL and SAIL

3842. PROF. RAM KAPSE: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for privatisation of Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) and Steel Authority of India Limited (SAIL) under consideration;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the specific reasons for privatisation of these two Government companies?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्राप्त होना

3843. **श्री शिव चरण सिंह:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश में उद्योग स्थापित करने के लिए विदेशों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संबंध में संयुक्त उद्यमों सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें राज्य-वार कितना-कितना निवेश किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या देश में इन उद्योगों की स्थापना से समग्रत: निकलने वाले परिणामों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) से (ग) 1 अगस्त, 1991 से 31 दिसम्बर, 96 तक की अवधि के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निदेश के कुल 10119 (वित्तीय तकनीकी) प्रस्ताव अनुमोदित किये गए हैं जिनमें 95591.71 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्ग्रस्त है। इन विदेशी सहयोग संबंधी प्रस्तावों के राज्य वार ब्यौरे विवरण में दिये गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

ऐसे प्रस्तावों के ब्यौरे अर्थात् विदेशी सहयोगी का नाम तथा देश, अन्तर्ग्रस्त इक्विटी निवेश, विनिर्माण की मद/कार्यकलाप भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा मासिक न्यूजलेटर के पूरक के रूप में प्रकाशित किये जाते हैं और इनकी प्रतियां नियमित रूप से संसद की लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं।

(घ) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन का पता लगाने के लिए एक अध्ययन शुरू किया है।

विवरण

अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान अनुमोदित विदेशी तकनीकी सहयोग तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	अनुमोदनों की संख्या		अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि	
	कुल	तकनीकी	वित्तीय	(करोड़ रुपये)
आन्ध्र प्रदेश	430	142	288	2425.32
असम	10	6	4	1.50
बिहार	66	39	27	130.75
गुजरात	539	294	245	3478.18
हरियाणा	399	140	259	1154.19
हिमाचल प्रदेश	70	48	22	329.68
जम्मू एवं कश्मीर	1	0	1	8.01
कर्नाटक	667	253	414	5164.98
केरल	98	36	62	517.00
मध्य प्रदेश	186	80	106	2797.70
महाराष्ट्र	1325	511	814	12492.98
मेघालय	1	0	1	2.50
नागालैण्ड	1	1	0	0.00
उड़ीसा	73	28	45	2737.19
पंजाब	101	39	62	802.64
राजस्थान	188	65	123	567.67
तमिल नाडु	790	263	527	5416.79
त्रिपुरा	1	0	1	0.68
उत्तर प्रदेश	383	171	212	2432.13
पश्चिम बंगाल	263	89	174	5163.03
अंडमान एवं निकोबार	5	0	5	0.98
अरुणाचल प्रदेश	2	0	2	11.06
चण्डीगढ़	14	2	12	72.46
दादर एवं नगर हवेली	47	31	16	69.83
दिल्ली	493	52	441	17216.98
गोवा	68	33	35	282.39
लक्ष्य द्वीप	1	0	1	0.50
पांडीचेरी	51	22	29	252.50
दमन एवं द्वीप	16	9	7	5.72
अन्य	3830	2110	1720	32056.37
कुल	10119	4464	5655	95591.71

FICCI's reservation over Exim Policy

3844. SHRI S.M. KRISHNA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether FICCI has recently expressed its reservation over the new Exim Policy which according to that organisation would lead to anti-dumping for small scale sector;

(b) if so, the reaction of Government thereto;

(c) whether his Ministry has conducted a survey regarding the import requirements of small scale sector; if so, the details and if not, the reasons therefor; and

(d) whether his Ministry have taken up the matter with Ministry of Commerce and in the process with W.T.O. to register its protest over the likely impact of anti-dumping on small scale sector of the country?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The FICCI, in a discussion paper prepared for a Round Table on Exim Policy: 1997&2002 held on 09th April, 1997, have expressed the view that as import liberalisation and tariff reductions are carried out, anti-dumping mechanism should be strengthened to guard against dumping of goods. The New Exim Policy has been announced only recently and it is yet too early to assess its impact on the small scale sector on issues of dumping and related matters. The Exim Policy provides for a institutional mechanism for anti-dumping measures that should take care of specific problems. The Exim Policy has liberalised the imports of 542 items. Out of these, only 5 product areas are reserved for production in the SSI sector which have been brought under the OGL. These items constitute a very small part of the total production and employment in the SSI sector.

(c) and (d) There is no comprehensive survey as such on the import requirements of the small scale industries sector in various product areas. The general view in this regard is that liberalisation of import procedures and opening up of import mechanisms help in improving the availability situation and distribution channels of various import materials at competitive prices. This is likely to be of benefit to the small scale industries sector which cannot deal in bulk purchases.